सिंह बिधूड़ी
पूर्व विधायक

OFFICE OF UDM
Dy No 2034
Date 15/5/12

सर्वश्रेष्ठ विधायक
तीसरी विधान सभा, दिल्ली
पूर्व अध्यक्ष
हरियाणा वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन
(सरकार का उपक्रम)

PS to UDM 14/5

4346

दिनांक : 03.05.2012

9/5/12
PS to UDM

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, सांई नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

मैं बदरपुर विधान सभा क्षेत्र का 10 साल तक विधायक रहा हूं और उक्त मीठापुर एवं जैतपुर वार्ड बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। मेरे विधायक कार्यकाल में ये दोनों नगर निगम वार्ड रेजिडेंशियल जोन में आते थे। परंतु नए जोनल-प्लॉन में इन्हें ओ-जोन में डाल दिया गया है, जिसके कारण इन वार्डों के निवासियों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाकर पुनः रेजिडेंशियल जोन में शामिल करवाने की कृपा करें। आभारी रहूंगा।

सादर,

भवदीय

(रामवीर सिंह बिधूड़ी)

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
PR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3729
Dated 30/5/12

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

2, गांव तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110044 • फोन : 011-29967384, मोबाइल: 9810004800

g) Integrated Destination Development Projects with Hotel facilities and Golf Centres.

h) Rural Tourism Projects

i) Cruise Liners for Tourism operating in Indian Rivers and Oceans

j) Adventure/Nature Tourism Projects

k) River cruise projects

l) Air Taxi Services

(xxvi) Master Plan of major cities should earmark commercial sites as hotel sites which should be allotted on long term lease. Annual lease rent to be calculated as a percentage on the value of the bids and be on a graded scale depending on the Star Category of the hotel property.

(xxvii) Shortage of hotel accommodation is a deterrent to development of tourism in various States. Construction of hotels is primarily a private sector activity which is highly capital intensive in nature and also has a long gestation period. Due to the high cost and low availability of land, hotels are opting for a higher star category as the setting up of budget hotels is not commercially viable.

(xxviii) In order to encourage the growth of budget accommodation, State Governments and the various Land Owning Agencies should create land banks, give land on long lease, allocate land on joint venture/ revenue sharing basis and also provide incentives and benefits to facilitate the growth of the accommodation sector in the country.

(xxix) Master Plan of major cities should earmark sites for convention (and Exhibition) centers which can be executed as PPP ventures or leased to the private sector for implementation.

(xxx) Evolve policies and programmes for synergizing partnerships between Archaeological Survey of India, State Archaeological Department and the private sector in the upkeep, management and marketing of monuments, forts, ancient temples and museums etc.

(xxxi) [redacted].

(xxxii) Local Bodies and Self Help Group should be actively involved in the management of tourist destinations in their jurisdiction. They should play the vital role of keeping the approach road to the destination clean and adoption of hygiene practices by various vendors at the tourist destination.